EDITORIAL

Turning Point

BSNL is a big PSU with 1.76 lakh employees and 39,000 employees are recruited by BSNL after formation on 01-10-2000. As on March 2018, BSNL owns land worth Rs. 70,000 crores and buildings worth Rs. 3760 crores. BSNL was posting operational profits during 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

In cut throat competition also, BSNL survived in the market in Mobile Sector. In January 2019, 9.86 lakh connections were added in the country without 4G, if the allotment of 4G Spectrum to BSNL as per the proposal submitted by BSNL in December 2017. The status of our entity will be quite different. In land line (Wire line / Broad Band) segment, BSNL is lagging behind. There were so many reasons in the present situation. (i.e. road widening, digging without intimation etc). We have to strive hard to protect our land line/Broad band customers in the competitive arena.

No doubt, The 'Turing point' in BSNL will emerge to save the entity at this crucial juncture with our untired work culture. The attitude of present Govt in centre is negative one. The Govt forgotten the commitment given on financial viability in Sept, 2000.

Now, the digital commission opinioned that 14000 crores were needed to get 4G spectrum to BSNL. The entire matter will be referred to "TRAI" to identify price and quantum spectrum to be allocated to BSNL with condition. " The apex decision making body at the DOT has taken a call that the revival of BSNL is important. Because it operates in strategic sector and therefore Govt presence in the Sector is desirable".

Unfortunately, the said entire thing is being linked with revenue of the company. The revenue is falling down continuously since 2009-10. It was drastically effected after entering the Reliance-Jio in the market in 2016, which supported by the Govt. The work force in BSNL is above 3.5 crore at the time of formation. All have taken absorption in BSNL form DOT, as per the agreement signed in 2000. BSNL, which has lowest debt of Rs. 13000 crores among all Telecom operators. Where 6.10 lakh crores debt are there in Telecom Sector among all Private operators. Within span of 5 to 6 years, above 60,000 employees will be retiring naturally.

In the scenario, the unions/associations in BSNL have proposed "Land management Policy" for the approval of DOT, for effective utilization/ leasing out of vacant land. If, the policy is approved, BSNL can earn Rs. 7,000 crores to Rs. 10,000 crores annually by leasing/renting out its vacant land. But, the DOT is deliberately blocking this proposal to ruin the BSNL.

The BSNL management has planned to outsource the maintenance of BSNL' towers, which were maintained by BSNL employees. There is no need for the company to spend such a huge amount at this point of time, when it is facing serious financial crisis.

BSNL unions/associations were making all out efforts to bring a "Turning point" in BSNL with hard and dedicated work culture. 'Niti Ayog,' TRAI and DOT have well plannedly coming in the way to abstract the crucial and needed "Turing Point' in the entity.

But, we proudly say the unity among the workers (Executive and Non-executives) in BSNL is very appreciable. There's firm motive is to defeat the hidden agenda of the present Govt in Centre (Close/Sale of BSNL) towards BSNL. The Govt is threatening the employees in the name of VRS/ CRS and estimating the costs to demoralize the workforce. Fact is fact, BSNL entity is in financial crunch with the policies of Govt. No fault at the part of employees. Employees are committed to bring the "Turning point in BSNL" to save BSNL and its employees, for which all the unions and associations of BSNL are on regular struggle. We, the NFTE has always seen in forefront of the struggles.

नये मोड़ पर

भारत संचार निगम लिमिटेड एक बड़ी लोक उपक्रम है, जिसमें 1.76 लाख समाहित कर्मचारी एवं 39,000 कर्मचारी कंपनी द्व ारा 1–10–2000 मसलन निगम के स्थापना के बाद नियुक्त किये गये हैं। इस कंपनी की जमीन की कीमत रू. 70,000 करोड़ आंकी गई है, तथा भवनों की कीमत तीन हजार सात सौ साठ (रू. 3760) आंकी गई है। निगम वर्ष 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 में संचालन लाभ अर्जित करते रही है। निजी कंपनियों के कठोर मुकाबले में भी बी.एस.एन.एल अच्छी प्रदर्शन के साथ आगे बढ़ते रही है। यहां जनवरी 2019 में भी कर्मियों के अथक प्रयास से 9.86 लाख मोबाइल कनेक्शन जोड़ने में सफलता हासिल की है। ऐसा तब है जब सभी वर्तमान निजी कंपनी फोर–जी स्पेक्ट्रम के साथ बाजार में हैं, अगर बी.एस.एन.एल. को भी आवंटित कर दी जाती तो स्थिति कुछ और देखी जाती। हमारे मूल सेवाएं लैंडलाइन, ब्रॉड–बैंड इत्यादि भी सड़क चौड़ीकरण, नालों का पुनरूद्धार आदि के कारण भूमिगत केबल के क्षत–विक्षत होने के वजह से पिछड़ रही है। हमें कठोर श्रम एवं मानसिक संतुलन के साथ इन सेवाओं को बनाये रखने के साथ आगे भी बढ़ाना है। प्रतिस्पर्धा के इस कठोर दौड़ में हमें संभलकर चलना पड़ेगा।

इसमें संदेह नहीं है कि नये मोड़ पर खड़े होकर हमें बड़े मुस्तैदी से मुड़ना है। हमें विश्वास है कि हमारी एकताबद्ध कार्य संस्कृति के द्वारा हम इस मुसीबत के दौर से निकल पायेंगे। केंद्र सरकार कंपनी के लिए नकारात्मक रवैया अपना रही है। सरकार सितंबर, 2000 में दिये गये वचनबद्धता को भूल रही है जहाँ इन्होंने कंपनी को आर्थिक जीवंतता जारी रखने सहित कई जिम्मेदारियों का लिखित वचन दिया था। अभी डिजीटल संचार आयोग ने फोर–जी स्पेक्ट्रम के लिए रू. 14000 करोड़ लागत की बात करती है। कहा जा रहा है कि फोर–जी स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए (टीआरएआई) दूरसंचार नियामक प्राधिकरण से राय मांगी जा रही है। ऐसी सूचना है कि दूरसंचार आयोग में उच्च स्तरीय निर्णय देने वाली समिति ने बी.एस.एन.एल को बनाये रखने की बात कही है क्योंकि यह कंपनी युद्ध संबंधित कुटनीतिक क्षेत्र में काम करती है।

दु:खद है कि बी.एस.एन.एल की स्थिरता और इसके उत्थान की बात राजस्व के साथ जोड़ कर देखी जा रही है। सरकारी कंपनी को सरकार आर्थिक रूप से संबल बनाने के बजाय इसके द्वारा प्राप्त राजस्व का हवाला देती है। यह सत्य है कि वर्ष 2009–10 से लगातार राजस्व में गिरावट आई है, परंतु हम 2014–15 से इस दिशा में घनात्मक अग्रसर होने लगे थे कि सरकारी संरक्षण प्राप्त रिलायंस–जियो का पदार्पण सितंबर 2016 में हुआ और उसके गैर वाजिब व्यापारिक संरचना के कारण दूरसंचार क्षेत्र में आपातकालिक स्थिति उत्पन्न हो गई। एक दर्जन से अधिक कार्यरत निजी कंपनियों में सिर्फ चार आज मैदान में हैं, परंतु बी.एस.एन.एल अपने मजबूत कार्य बल के कारण इस संकट में भी टिकी रही हैं।

दूरसंचार प्रचालन एवं दूरसंचार सेवा विभाग को निगम में परिवर्तन के समय 350000 कर्मचारियों ने निगम में शामिल होने का विकल्प दिया था। आज 1.76 लाख कर्मी हैं जो अगले पांच साल में 60,000 की संख्या में सेवानिवृत्त हो जायेंगे।

ज्ञातव्य है कि बी.एस.एन.एल पर लगभग 14000 करोड़ रूपये के बैंक कर्ज है। जबकि दूरसंचार क्षेत्र में बैंक ऋण लगभग 6.10 लाख करोड़ है। ये समस्त पैसे जनता के हैं, जो निजी कंपनियों के झोली में डाल दिये गये है, परंतु बी.एस.एन.एल को मुसीबतों से निकलने के लिए ऋण लेने की अनुमति दूरसंचार विभाग जारी नहीं कर रही है।

बी.एस.एन.एल के श्रमिक संघों एवं अधिकारियों के संगठनों ने बी.एस.एन.एल की जमीन का "भूमि प्रबंधन नीति" लागू करने का अधिकार बी.एस.एन.एल को देने की मांग की है। अगर सरकार इस दिशा में अनुमति देती है तो यह कंपनी अपनी खाली पड़ी जमीनों को लीज या किराये पर देकर प्रति वर्ष 7000 से 10,000 रूपये तक राजस्व प्राप्त कर सकती है। दूरसंचार विभाग में बैठे कतिपय अधिकारियों की कुटिलता के कारण इस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। इधर बी.एस.एन.एल प्रबंधन भी कुछ घातक कार्यवाइयां कर रही है, मसलन समस्त टावर का रखरखाव एवं संचालन बिना श्रमिक संघों से वार्ता किये ही निजी बाह्य कंपनियों को दे दी है। जो सर्वथा निंदनीय है। जो कार्य हमारे अपने कर्मी निपटाते थे उसे निजी घरानों में सौंपने के पीछे कौन–सी मानसिकता कार्य कर रही है, ये प्रबंधन ही बता सकती है।

बी.एस.एन.एल के समस्त श्रमिक संघों एवं अधिकारियों के संगठन एकताबद्ध होकर "नये मोड़" से धनात्मक दिशा में मुड़कर कंपनी को तरक्की की नया आयाम जोड़ना चाहते हैं परंतु नीति आयोग, टी.आर.ए.आई एवं डी.ओ.टी इस कंपनी को डुबो देने के लिए कटिबद्ध है।

हमें गर्व है कि बी.एस.एन.एल के सभी कर्मचारी एवं अधिकारी कंपनी की रक्षा हेतु संकल्पित हैं। यह एक सराहनीय पहल है। इस एकताबद्ध समूह का संकल्प है कि हम सरकार के उन नीतियों को विफल करेंगे जो छुपे रूप से कंपनी को समाप्त कर देने के लिए चलाई जा रही है। सरकार की ओर से बी.आर.एस/सी.आर.एस एवं अन्य तरह के भय का वातावरण पैदा करने की कोशिश की जा रही है। यह सत्य है कि कंपनी घोर आर्थिक संकट में है परंतु इसके लिए सरकार की उदासीनता एवं उसकी नीतियां जिम्मेवार है। कर्मचारी एवं अधिकारी बी.एस.एन.एल की रक्षा एवं उत्थान के लिए लगातार संघर्ष पर हैं तथा एन.एफ.टी इसमें अग्रणी भूमिका निभा रही है।